2. Consideration and passing of the following Bills, after they have been passed by the Lok Sabha:--

(a)	The Constitution Scheduled Castes Orders (Amendment) Bill, 2001.	1 Hour
(b)	The Negotiable Instruments (Amendment and Miscellaneous Provisions) Bill, 2002.	1 Hour
(c)	The Refugee Relief Taxes (Abolition) Repeal Bill, 2002.	Half-an-hour
(d)	The Biological Diversity Bill, 2002.	4 Hours
(e)	The Imperial Library (Indenture Validation) Repeal Bill, 2002.	Half-an-hour
(f)	The Companies (Second Amendment) Bill, 2001.	2 Hours

3. Consideration and return of the Appropriation Bills relating to the following Demands:--

(a)	Supplementary Demands for Grants (Railways) for 2002-2003.	3 Hours (to be discussed together)
(b)	Demands for Excess Grants (Railways) for 1999-2000.	

ANNOUNCEMENT REGARDING GOVERNMENT BUSINESS

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT AND POVERTY ALLEVIATION (SHRI O. RAJAGOPAL): Sir, I beg to announce that the Government Business in this House, for the week commencing 29th July, 2002, will consist of --

1. Consideraton of any item of Government Business carried over from today's Order Paper.

Consideration and passing of the following Bills:--

(a) The General Insurance Business (Nationalisation) Amendment Bill, 2002, as passed by the Lok Sabha.

(b) The Insurance Amendment Bill, 2002, as passed by the Lok Sabha.

(c) The Petroleum (Berar Extension) Repeal Bill, 2002.

(d) The Suppression of Unlawful Acts against Safety of Maritime Navigation and Fixed Platforms on Continental Shelf Bill, 2002.

3. Consideration and passing of the the Pre-natal Diagnostic Techniques (Regulation and Prevention of Misuse) Amendment Bill, 2002.

4. Consideration and passing of the following Bills, as passed by the Lok Sabha:--

(a) The Offshore Areas Mineral (Development and Regulation) Bill, 2002.

(b) The Delhi Municipal Corporation (Validation of Electricity Tax) Act and Other Laws (Repeal)Bill, 2002.

5. Discussion on the Statutory Resolution seeking disapproval of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Ordinance, 2002, and consideration and passing of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Bill, 2002, after it has been passed by the Lok Sabha.

6. Consideration and passing of the following Bills after they have been passed by the Lok Sabha:-

(a) The Negotiable Instruments (Amendment and Miscellaneous Provision) Bill, 2002.

(b) The Refugee Relief Taxes (Abolition) Repeal Bill, 2002.

(c) The Companies (Second Amendment) Bill, 2001.

(d) The Biological Diversity Bill, 2000.

7. Consideration and return of the Appropriation Bills relating to the following Demands:-

(a) Supplementary Demands for Grants (Railways) for 2002-03.

(b) Demands for Excess Grants (Railways) for 1999-2000.

SPECIAL MENTIONS

Flood situation in Bihar

प्रो. राम देव भंडारी (बिहार): माननीय सभापति जी, मैं विशेष उल्लेख के माध्यम से पुनः उत्तरी बिहार में भीषण बाढ़ से संबंधित अति महत्वपूर्ण सवाल को सदन में उठा रहा हूं। महोदय, उत्तरी बिहार एक बार फिर भयंकर बाढ़ की चपेट में है । स्थिति गंभीर एवं भयावह है । नेपाल में भारी वर्षा तथा वहां की नदियों से नेपाल द्वारा छोड़े गए पानी की वजह से बाढ़ का यह भीषण प्रकोप हुआ है ।

केन्द्रीय जल आयोग के अनुसार राज्य की छः प्रमुख नदियां कोसी, कमला-बलान, गंडक, महानन्दा, बागमती, अधवारा समूह खतरे के निशान से काफी ऊपर बह रही हैं । बिहार के मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, मुजफ्फरपुर, सहरसा, शिवहर, सीतामढ़ी सहित अन्य कई ज़िले इस विनाशकारी बाढ़ से प्रभावित हैं । कमला-बलान का तटबंध आधा दर्जन जगहों पर टूट गया है । झंझारपुर अनुमंडल, जहां मेरा घर है, वहां के दर्जनों गांवों में पानी भर गया है । झंझारपुर रेलवे स्टेशन में भी पानी भरा हुआ है । सड़कों पर भी घुटनों और कमर तक पानी है । इस समय यह अनुमंडल राज्य के दूसरे हिस्सों से कट सा गया है । उधर भुतही-बलान का पश्चिमी तटबंध टूट जाने से फुलपरास अनुमंडल के गांवों में भी पानी भर गया है ।

रेल लाइनों पर पानी भर जाने से दरभंगा-झंझारपुर-निर्मली तथा दरभंगा-नरकटियागंज खंड पर रेलों का आना-जाना बंद है । आवागमन पूरी तरह छिन्न-भिन्न है । कई लाख लोग बाढ़ की वजह से प्रभावित हैं और वे घर-बार छोड़ कर ऊंची जगहों पर शरण लिए हुए हैं । हज़ारों एकड़ में लगी खरीफ की फसल बाढ़ में बरबाद हो गई है । जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है । करोड़ों रुपए की क्षति हुई है । राज्य सरकार पूरी क्षमता से युद्ध स्तर पर बचाव एवं राहत का कार्य कर रही है । राज्य की माननीया मुख्य मंत्री श्रीमती राबड़ी देवी ने 24 जुलाई को हवाई सर्वेक्षण कर स्थिति का जायज़ा लिया है तथा तुरंत बचाव व राहत कार्य के लिए आवश्यक निर्देश